

15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन : योगी

दुर्जन के लिए जीरो टॉलरेंस

गोरखपुर 27 मार्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर माहौल के साथ सरकार रामराज्य की अवधारणा को साकार कर रही है।

योगी गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को कन्या पूजन के बाद प्रदेशवासियों को वास्तविक नवरात्र की नवमी तिथि एवं श्रीरामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां हर सज्जन शक्ति का संरक्षण है लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना



है लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में विरासत का सम्मान भी है और विकास को गारंटी भी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य की अवधारणा से बिना

भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने के अवसर प्रदान किए हैं।

हर एक क्षेत्र में विकास के साथ प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय एवं 65 लाख परिवारों को पीएम.सीएम.सीएम योजना का लाभ मिला है। 19 से 10 करोड़ लोगों को पीएम.सीएम जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई है।

सुख, समृद्धि और सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली पावन तिथि

मुख्यमंत्री ने नवरात्र नवमी पर मंगलकामना करते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल नवमी, वासंतिक नवरात्र की सिद्धि प्रदान करने वाली, सुख, समृद्धि और सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली पावन तिथि है। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्रीराम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए सदैव से प्रेरणा रहें हैं।

आज का इतिहास

- 1795 - पोलैंड का तीसरा विभाजन हुआ।
- 1809 - मेंडलिन युद्ध में फ्रांस के हाथों स्पेन की हार हुई।
- 1854 - क्रोमियाई युद्ध के दौरान फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1891 - विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित किया गया।
- 1917 - प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान पहली बार महिलाओं की सेना सहायक कोर की स्थापना।
- 1923 - फ्रांसीसी इटली की वायु सेना रिजिया एरानोटिका की स्थापना की गई।
- 1930 - तुर्की में राजधानी अंगोरा का नाम बदलकर अंकारा और कॉन्स्टांटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल किया गया।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार बेहद जरूरी : जयशंकर

फ्रांस में जी-7 बैठक - भारत ने रखी मजबूत बात

नई दिल्ली, 27 मार्च। फ्रांस में आयोजित जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और नार्को-आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिरता के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार बेहद जरूरी है। एस. जयशंकर ने अपने संबोधन में नार्को-आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस



पर सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान उन्होंने कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

नासिक में 'बाबा' का काला खेल उजागर 6 करोड़ रुपए की टगी, यौन शोषण के आरोपों से सनसनी

डर दिखाकर वसूली, विदेश यात्राओं का जाल स्वयंभू बाबा पर महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप

मुंबई, 27 मार्च। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताकर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी अशोक खरात का मामला अभी ताजा ही था कि एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है।

महाराष्ट्र के वसई में एक महिला ने एक स्वयंभू बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला (35) का आरोप है कि आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भगवान महादेव का अवतार है

भारत ने बांग्लादेश के साथ खड़ा होकर पाक पर साधा निशाना

नई दिल्ली। भारत ने 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान के अत्याचारों के लिए न्याय की दिशा में बांग्लादेश के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान पहले भी और अब भी युद्ध के दौरान के नरसंहार और अपराधों में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां साप्ताहिक ब्रीफिंग में इससे संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि हम सभी 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाक द्वारा किए गए अत्याचारों से अवगत हैं। उन्होंने कहा, इस नरसंहार में लाखों निर्दोष बांग्लादेशियों की सुनियोजित और लक्षित हत्या शामिल थी।

देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं : सरकार

रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवरी देश में स्थिति सामान्य घरेलू उत्पादन और आयात से गैस आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित



इससे दैनिक उत्पादन बढ़कर 50 टोएमटी तक पहुंच गया है, जो देश की कुल आवश्यकता का 60

नई दिल्ली, 27 मार्च। देश में एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है तथा कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है।

मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में लागू किए गए नियंत्रण उपायों के बाद घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हाल के दिनों में घबराहट के कारण मांग बढ़कर 89 लाख सिलेंडर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और मांग फिर से संतुलित स्तर पर आई है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं। इसके साथ ही, पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने की नीति भी जारी है, जिसे सस्ता, स्वच्छ और सुरक्षित इंधन माना जाता है।

मोदी का नेतृत्व देश के लिए सिद्ध हो रहा है सुरक्षा कवच : भजनलाल

देश के लाखों परिवारों को आर्थिक संवल मिलेगा वैश्विक उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता से मुक्त रहेंगे

जयपुर 27 मार्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हो रहा है।

शर्मा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने पर शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 13 रुपये से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य करने का



निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील कदम से देश के लाखों परिवारों को आर्थिक संवल मिलेगा। साथ ही वे वैश्विक उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी नागरिक अफवाहों से दूर रहें और एकजुट होकर राज्य एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग दें।

पंजाब में 10 लाख तक मुफ्त इलाज : केजरीवाल

किसानों-मजदूरों के लिए बड़े अस्पतालों के दरवाजे खुले पंजाब मॉडल पर केजरीवाल का जोर, गुजरात को दी सलाह

चंडीगढ़, 27 मार्च। पंजाब में एक कार्यक्रम के दौरान अरविन्द केजरीवाल ने अपनी सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा दावा किया।

उन्होंने कहा कि अब राज्य में किसानों और मजदूरों को भी बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जहां पहले केवल अमीर लोग ही इलाज करा पाते थे।

केजरीवाल ने पंजाब मॉडल को उदाहरण बताते हुए कहा कि किसानों को खेती के लिए मुफ्त



बिजली दी जा रही है और फसल का भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जा रहा है।

राजनीतिक बदलाव जरूरी है। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के वोट से नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, जबकि आम जनता के बच्चों को समान अवसर नहीं मिलते। पंजाब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अरविन्द केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सिवाई के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं, किसानों और मजदूरों को मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब में बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी किसानों और मजदूरों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

इमरान खान की सजा को निलंबित करने वाली याचिका पर 31 को सुनवाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 240 मिलियन डॉलर (190 मिलियन पाउंड) के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ओर से अपनी सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश सरदार मोहम्मद सरफरान डोगर और न्यायमूर्ति मोहम्मद आसिफ की खंडपीठ उनकी सजा को निलंबित करने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस्लामाबाद की एक अदालत ने 17 जनवरी, 2025 को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल और बुशरा बीबी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

विमान रखरखाव के लिए 858 करोड़ का अनुबंध

नई दिल्ली 27 मार्च। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए विमान रोधी तंत्रिका वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद और लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8आई के निरीक्षण (डिपू स्तर) के लिए कुल 858 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर यहां रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किये गये। मंत्रालय ने बताया कि सेना के लिए 445 करोड़ रुपये की लागत से तंत्रिका वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध रूस की जेएससी रोसाबोरोनएवसपोर्ट के साथ किया गया है।

अमित शाह शनिवार को ममता सरकार के खिलाफ जारी करेंगे व्यापक आरोप पत्र

तृणमूल के भीतर कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर

कोलकाता, 27 मार्च। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र की घोषणा कर सकते हैं। शाह के शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है।

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि आरोप पत्र की घोषणा पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को चिह्नित करता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ भाजपा पत्राधिकारी ने कहा, यदि आरोप पत्र तृणमूल के भीतर कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो घोषणा पत्र उसके जवाब में व्यापक समाधान

प्रस्तुत करेगा। साथ मिलकर, ये दो पहल सत्ताधारी पार्टी की आलोचना को और तेज कर देंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, श्री शाह का विमान शुक्रवार देर रात करीब 11-40 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वह न्यू टाउन के एक होटल में जाएंगे। शाह शनिवार दोपहर 12 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ औपचारिक रूप से 14-सूत्रीय व्यापक आरोप पत्र जारी करने की उम्मीद है।

प्रारंभ में, भाजपा ने श्री शाह के इस दौरे के दौरान पार्टी का 'चुनावी घोषणा पत्र संकल्प' पत्र जारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि, रणनीति में संशोधन किया गया है और अब पहले आरोप पत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिये चलाया जागरूकता अभियान

नयी दिल्ली/कोलकाता, 27 मार्च। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए शुक्रवार से राज्यभर में विशाल अभियान की शुरुआत की। आयोग ने चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व थीम पर आयोजित इस अभियान के तहत हावड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोग की मौजूदगी में फेरी घाट पर समापन हुई। आयोग के इस अभियान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकगीत, नृत्य और नुकड़ नाटकों के माध्यम से मतदान के महत्व को दर्शाया गया। इसके साथ ही नावों के जरिए फेरी सेवा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में लोकप्रिय एनिमेटेड पात्र 'छोटा भीम' और 'छुटकी' की मौजूदगी ने खासकर युवाओं और नए मतदाताओं को आकर्षित किया और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना, उन्हें मतदान केंद्र, समय और प्रक्रिया की जानकारी देना है। खासतौर पर शहरी मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों पर फोकस किया जा रहा है।

ईडी ने एसईसीएल अधिकारी की 83.24 लाख की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), कोरबा (छत्तीसगढ़) के सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षण) प्रभाकर शुक्ला और उनके परिवार से जुड़ी 83.24 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने की घोषणा की है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई सीबीआई (एसबीबी), जबलपुर द्वारा प्रभाकर शुक्ला के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में सामने आया कि कुर्क मार्च 2008 से 30 नवंबर 2022 के बीच शुक्ला ने अपनी वैध आय से लगभग 39.83 प्रतिशत अधिक यानी 83.24 लाख की अवैध संपत्ति जुटाई।

उत्तर गुजरात के विकास को मिलेगी नई गति

अहमदाबाद, 27 मार्च। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2025 को गुजरात दौरे के दौरान 1,400 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। जिसमें बेच राजी-रगुजरे लखंड भी शामिल था, जिस का ब्रॉड गेज में परिवर्तन कार्यपूर्ण हो चुका है। लगभग 40 किलो मीटर लंबाई एवं 520 करोड़ की लागत से सम्पन्न इस परियोजना के माध्यम से उत्तर गुजरात को सुदृढ़ रेल संपर्क प्रदान किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षित, तेज एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।



इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डायरेक्टर जी-राइड श्री राजकुमार, जौएम (सिविल) श्री शिवेन्द्र कुमार, अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफा) मंत्री मीणा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनू त्यागी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. जेनिया गुप्ता तथा वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री वैभव सकलेवा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महसूना लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री हरिभाई पटेल के साथ दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्हें बेचराजी-रगुज रेल खंड के सीआरएस निरीक्षण हेतु प्रेषित प्रस्ताव, वर्तमान प्रगति एवं आगामी यात्री सेवाओं के संचालन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम किसानों की आय में औसतन 6,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि हुई

खेती में उछाल, 39 प्रतिशत तक योगदान : शिवराज

नई दिल्ली, 28 मार्च। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य सभा में बताया कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश में शुष्क और वर्षा-निर्भर क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन में 82 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई और कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में शुष्क क्षेत्रों का योगदान 29 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत तक हो गया है।

मन्त्री सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि देश में लगभग 48 प्रतिशत कृषि शुष्क या वर्षा-निर्भर है और मौजूदा सरकार ने इसकी उपज



बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में इनका योगदान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न उत्पादन तो तेजी से बढ़ा, लेकिन शुष्क (ड्राईलैंड) क्षेत्र अपेक्षाकृत अछूते रह गए थे।

चौहान ने बताया कि हैदराबाद स्थित केंद्रीय बरानी/शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चलायी जा रही समन्वित परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रभाव के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में यह सामने आया कि मौसम आधारित सलाह से किसानों की आय में औसतन 6,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि हुई है। खेत-तालाब, चेक-डैम, स्ट्रॉच-डैम, बोरी-बंधन जैसी जल संधान तकनीकों के कारण प्रति खेत-तालाब लगभग 73,895 रुपये तक अतिरिक्त आय दर्ज की गई।

संस्थान के 18 मुख्य, 1 उप और 9 स्वायत्त केंद्र हैं। इसके अलावा 25 मुख्य और 5 स्वायत्त केंद्र भी देशभर में स्थापित हैं, जिनमें महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र भी शामिल हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में फसल अनुसंधान संस्थानों ने पिछले 10-11 वर्षों में 3,236 जलवायु-अनुकूल कृषि कार्यों का विकास किया है, जो कम पानी, अधिक तापमान और अधिक सर्दी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं।

तमिलनाडू से 273.71 करोड़ जल

234 निर्वाचन क्षेत्रों में पलायन स्कायड और निगरानी

चेन्नई। तमिलनाडू विधानसभा चुनाव से पहले इसी ने निगरानी को सख्त करते हुए अब तक 273.71 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और अन्य सामान जब्त किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक के अनुसार, इस जब्ती में 44.89 करोड़ रुपये नकद, 116.07 करोड़ रुपये के कीमती धातु, 7.60 करोड़ रुपये के इस्त्र, 0.93 करोड़ रुपये की शराब और 104.20 करोड़ रुपये के उपहार व अन्य वस्तुएं शामिल हैं। राज्य में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने व्यापक स्तर पर निगरानी व्यवस्था

लागू की है। इसके तहत 234 निर्वाचन क्षेत्रों में पलायन स्कायड और निगरानी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सामान्य, पुलिस और व्यव्य पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। आयोग ने यह भी बताया कि 6.48 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिनकी जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसी ने अतिरिक्त गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 273.71 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और अन्य सामान जब्त किया है।

कांग्रेस ने नामांकन वापस न लेने वाले 6 उम्मीदवारों को निलंबित किया

पुडुचेरी। पुडुचेरी में कांग्रेस ने छह बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित करके अपना संकट टालने की कोशिश की है। पार्टी ने सख्तियों दलों को आवंटित छह सीटों (पांच द्रमुक को और एक वीसीके को) पर अपनी दावेदारी करते हुए नामांकन दाखिल करने और वापस न लेने वाले सभी छह उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के छह उम्मीदवारों ने नाम वापसी की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त होने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लिया था।

चुनाव आयोग ने बंगाल में 14 और रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया

कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच तबादलों का सिलसिला जारी रखते हुए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में नियुक्त 14 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को बदल दिया है। ये सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति के मात्र पांच दिन बाद ही हटाए गए हैं, जिससे आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। इस समाह की शुरुआत में आयोग ने 20 जिलों के 73 चुनाव क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट भी शामिल थी। सुश्री बनर्जी ने भवानीपुर में आरओ के रूप में नंदीग्राम के बीडीओ सूरजित राय की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।